पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के टोंक आगमन पर रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता अकबर खान ने 51 किलो की माला पहनाकर पायलट का जोरदार स्वागत किया।

सचिन पायलट टोंक पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

सचिन पायलट ने टोंक के गांवों का दौरा किया और अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का जायजा लिया

- सचिन पायलट ने किसानों से बात की और कहा कि, समय रहते और जल्द से जल्द किसानों को मुआवज़ा दिलाया जाएगा।
- जिला कलैक्टर और एस.पी. सहित सभी आला अधिकारी मौजूद थे।

टोंक, 11 अक्टूबर (निसं)। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और टोंक विधायक सचिन पायलट देर रात्रि झालावाड़ से टोंक पहुँचे, पायलट ने टोंक सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। सुबह सर्किट हाउस में ही जनसुनवाई की और अधिकरियों की बैठक भी ली। पायलट के टोंक आगमन पर रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समाजिक न्याय संगठन राष्ट्रीय संयोजक अकबर खान ने उनका 51 किलो की माला पहनाकर अभिनन्दन किया।

इसके बाद पायलट ने अपनी टोंक विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। पायलट ने इस दौरान ग्राम ठीकरिया, अरनिया तिवाडी, अरनिया केदार, कारीरिया, बालापुरा, देवपुरा व सोरण सहित आधा दर्जन से अधिक ग्रामों का भ्रमण किया और किसानों से बात की। इस दौरान किसानों ने अपनी नष्ट हुई फसलों की जानकारी दी। पायलट ने जिला कलैक्टर चिन्मयी गोयल सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पायलट ने किसानों से कहा कि उन्हें अपनी फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द और समय रहते मिलेगा।

मीडिया से बात करते हुए पायलट ने बताया कि किसानों की खड़ी फसलें ही नहीं, कटी फसलें भी खराब हो गई हैं। उनके पास चारे का भी साधन नहीं बचा है। सभी की जल्द गिरदावरी करा सभी तरह से किसानों को आर्थिक मदद मिले ये हमारी कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि "टोंक जिलें में ही नहीं हाड़ौती के जिलों में भी अतिवृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इससे बुआई का समय भी निकल रहा है, खाद व डीएपी की भी किल्लत है। इसके लिए कृषि मंत्रालय में बात की है। खाद व डीएपी की मात्रा को भी बढ़ाएंगे।" उन्होंने कहा कि "इस मुश्किल घड़ी में मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। क्लेम के लिए किसान ऑफ लाइन भी लिखित में दे सकते हैं, 72 घंटे के भीतर उनकी शिकायत रजिस्टर्ड करवाई जाएगी। जिला कलैक्टर को इसके लिए निर्देशित किया है। पूरी ताकत के साथ हम किसानों के साथ खड़े है।"

इस मौके पर जिला कलैक्टर चिन्मयी गोपाल, टोंक एसपी मनीष त्रिपाठी, एसडीएम टोंक गिरधर, तहसीलदार रामधन गुर्जर, कृषि विभाग टोंक के उपनिदेशक राधेश्याम मीणा, मदरसा बोर्ड के सदस्य सऊद सईदी, निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गाता, नगर परिषद टोंक के सभापति अली अहमद, उपसभापति बजरंगलाल वर्मा, सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज फागणा, शिवजीराम मीणा, फौजूराम मीणा आदि मौजूद थे। पायलट का ग्राम शिवपुरी, ठिकरिया, अरनिया केदार, करीरिया के ग्रामीणों ने स्वागत किया तथा अपनी समस्या बताई। इस अवसर पर सचिन पायलट ने ग्राम अरनिया तिवाडी, बालापुरा में खेतों में जाकर फसल खराबे की जानकारी ली।

मुलायम के जाने के बाद सपा का विभाजन रूक सकेगा?

शिवपाल, आजम खान व मायावती मिलकर मुलायम सिंह की विरासत पर कब्जा कर लेंगे?

- मुलायम सिंह ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र अखिलेश को उत्तराधिकारी घोषित तो कर दिया था। पर अब ऐसा प्रचार हो रहा है कि, अखिलेश के कामकाज से स्वयं मुलायम भी थोड़ा खिन्न थे, अपने अंतिम दिनों में। शिवपाल व उनका समूह, जिसमें आज़म खान व अमर सिंह भी थे, एक समय प्रचारित करने लगे थे कि, जिस जल्दबाजी से मुलायम सिंह को सपा के अध्यक्ष पद से हटाया गया व मुलायम सिंह के पुराने साथियों को घर भेजा गया, उससे अखिलेश औरंगज़ेब हो गये हैं।
- बहरहाल, अखिलेश के समक्ष इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी मैनपुरी संसदीय सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रख सके।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। मुलायम सिंह यादव के युग के अवसान के साथ ही, समाजवादी पार्टी एक बार फिर विरासत के युद्ध की तरफ बढ़ती प्रतीत हो रही है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के इस स्वर्गीय संस्थापक एवं दिग्गज नेता के भाई शिवपाल यादव पार्टी को तोड़ने का पूरा-पूरा प्रयास कर सकते हैं। उनकी तमाम स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों तथा पिछली तीन साल में सक्रिय राजनीति को अलविदा कह देने के बावजूद, मुलायम की मौजूदगी मात्र से ही यह तो सुनिश्चित था ही कि पार्टी के प्रथम परिवार के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच एक हद तक सामान्य शिष्टाचार बना रहेगा। जहाँ उत्तराधिकार का मुद्दा मुलायम के जीवन-काल में ही अखिलेश यादव के पक्ष तय हो गया था, वहीं जो स्थिति उभर कर सामने आई थी, उसमें सपा-संस्थापक स्वयं को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। वस्तुत:, अखिलेश ने अपने पिता को सपा के अध्यक्ष पद से हट जाने के लिये बाध्य कर दिया था तथा बहुत से पुराने दिग्गजों, जिनमें आज़म खान, शिवपाल तथा स्व. अमर सिंह भी शामिल थे, को दरकिनार कर दिया था। अखिलेश के कार्यों ने उन्हें औरंगज़ेब का प्रतिरूप बना दिया था, जिसने सम्राट बनने के लिये अपने पिता को कैद कर दिया था।

ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि शिवपाल गुट आगामी सप्ताहों तथा महीनों में इस पूरे घटनाक्रम का लाभ लेना चाहेगा।

ऐसी चर्चा है कि शिवपाल, आज़म तथा मायावती की तिकड़ी अखिलेश के नेतृत्व वाले अधिकृत सपा गुट को चुनौती देने के लिए एकजुट होने की कोशिश में हैं।

ऐसे समय पर, जब नरेन्द्र मोदी द्वारा संचालित भाजपा, सपा के पुराने गढ़ों में उसे खत्म करने में जुटी हुई है, अखिलेश के सामने पहली और बहुत बड़ी चुनौती यह होगी कि वे मैनपुरी लोकसभा को बरकरार रखें, जो उनके पिता के पास रही थी। मुलायम 10 बार विधायक तथा 7 बार सांसद रहे थे। इस सात अवसरों में वे पाँच बार मैनपुरी लोकसभा सीट से ही जीते थे। जिस बार वे चुनाव नहीं लड़े थे, सपा प्रत्याशी इस सीट से जीता था। यही स्थिति उन अन्य चुनाव क्षेत्रों में भी रही, जो सपा का गढ़ मानी जाती थीं। इस साल आज़मगढ़, जो सपा का गढ़ माना जाता है, सीट के लिये उपचुनाव में, भाजपा के दिनेश लाल यादव ने यह सीट सपा से छीन ली थी। कन्नौज, जो सपा का एक अन्य गढ़ मानी जाती थी तथा जिसका प्रतिनिधित्व मुलायम, अखिलेश एवं डिम्पल यादव ने भी किया था, 2019 से भाजपा के पास है।

2019 में, यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत ठाकुर ने डिम्पल यादव को हराया था। सम्भल भी परम्परागत रूप से सपा का गढ़ रहा था, लेकिन यहाँ भी सपा की पकड़ कमजोर हो गई तथा 2009 में शफीकुर रहमान बर्क, जो उस समय बसपा प्रत्याशी थे, ने यह सीट सपा से छीन ली थी इस बीच, सपा रामपुर लोकसभा सीट भी हार गई है, जिस पर आज़म खान 2019 में जीते थे। ऐसी पाँच सीटों, जिन पर 2019 में सपा जीती थी, में से वह दो सीटें- आज़मगढ़ और रामपुर हार चुकी है। मुलायम की मृत्यु के साथ ही लोकसभा में सपा सांसदों की संख्या 5 से घटकर 2 रह गई है।

प्रधानमंत्री ने 900 मीटर में बना भव्य महाकाल कॉरीडोर राष्ट्र को समर्पित किया

- उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में बने इस भव्य परिसर में 84 शिवलिंग, चार महावीर, छह विनायक, आठ भैरव, अष्ट मातृका, नवग्रह, 10 विष्णु, 11 रूद्र, 12 आदित्य, 24 देवियां और 88 तीर्थ हैं, जिनके केंद्र में राजाधिराज स्वयं महाकाल विराजमान हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी ने महाकालेश्वर के गर्भगृह में बैठकर करीब आधे घंटे पूजा-साधना की।

उज्जैन, 11 अक्टूबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बनाए गए आध्यात्म और तकनीकी के अद्भुत संगम महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया।

मोदी ने लगभग 900 मीटर लंबे भव्य महाकाल लोक के प्रवेश द्वार नंदी द्वार पर रक्षा सूत्र से बनाए गए शिवलिंग का रिमोट दबा कर लोकार्पण किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मोदी परिसर में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कुछ देर टहले। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान उन्हें लगातार महाकाल लोक के बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दिए।

पैदल चलते हुए मोदी महाकाल लोक परिसर में बनाए गए त्रिपुरासर संहार के दृश्य, सप्तर्षि मंडल परिसर, नवग्रह परिसर और रूद्रसागर के समीप भी गए। हर स्थान पर प्रधानमंत्री विशेष रुचि लेकर यहां के विहंगम और नयनाभिराम दृश्यों का अवलोकन करते दिखाई दिए।

इसके बाद मोदी परिसर की सैर के लिए इलेक्ट्रिक वाहन में सवार हुए। इसी वाहन के माध्यम से उन्होंने पूरे महाकाल लोक की सैर की। महाकाल लोक में शिवपुराण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिनके बारे में वहां लगे बार कोड के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है। यहां 108 स्तंभ बनाए गए हैं, जिनमें शिव तांडव से जुड़ी जानकारी नक्काशी और भित्ति चित्रों के माध्यम से दी गई है। महाकाल लोक बुधवार से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि, सिंहस्थ के समय में उनके मन में जो विचार आए थे, आज उन्हें मूर्त रूप मिल गया है।

मोदी ने महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, पिछले सिंहस्थ के समय में उन्हें महाकालेश्वर भगवान का बुलावा आया। उन्होंने बेहद विनम्र लहजे में कहा कि, महाकाल का बुलावा आए तो बेटा आए बिना कैसे रह सकता था। उन्होंने कहा कि, उस दौरान उनके मन में लगातार मंथन का दौर चल रहा था। उसी मंथन में एक विचार इस कल्पना का भी आया था। उस समय का भाव आज चरितार्थ हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने महाकालेश्वर और उज्जयिनी नगरी की महिमा बताते हुए कहा कि यहां 84 शिवलिंग, चार महावीर, छह विनायक, आठ भैरव, अष्ट मातृका, नवग्रह, 10 विष्णु, 11 रूद्र, 12 आदित्य, 24 देवियां और 88 तीर्थ हैं, जिनके केंद्र में राजाधिराज महाकाल विराजमान हैं।

4.2 करोड़ लोगों ने आर.टी.आई. का इस्तेमाल किया

- ट्रांसपैरैंसी इंटरनैशनल की रिपोर्ट के अनुसार आर. टी. आई. के जरिये सबसे ज्यादा सूचनायें केन्द्र सरकार से मांगी गई हैं।

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (वार्ता)। सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से अब तक कुल 4.2 करोड़ लोगों ने सरकार की विभिन्न एजेंसियों से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम का इस्तेमाल किया है। देश में सूचना का अधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल इंडिया की इस छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान देश के सूचना आयोगों के समक्ष अब तक करीब 26 लाख द्वितीय अपील एवं शिकायत दर्ज की गयी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य स्तरीय सूचना आयोगों में कुल 165 पदों में दो मुख्य सूचना आयुक्त सहित 42 पद रिक्त हैं।

टी.आई.आई. द्वारा मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार सूचना के अधिकार के प्रयोग में सबसे ज्यादा सूचनाएं केंद्र सरकार और उसके संगठनों से मांगी गयी हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं केरल का स्थान है।रिपोर्ट के अनुसार आर.टी.आई. के तहत केन्द्र के बाद जिन सरकारों से सबसे ज्यादा जानकारियां मांगी गयीं।

बार चुनाव का रास्ता साफ

जयपुर, 11 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने देश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के गत तीन अक्टूबर के राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। ये चुनाव 18 नवम्बर को होने है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में बी.सी.आई., बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बी.सी.आई. में याचिका दर्ज करने वाले सुमेर सिंह ओला को नोटिस जारी कर पांच सप्ताह में जवाब तलब किया है।

जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रहलाद शर्मा व रोहन जैन सहित अन्य की याचिका पर दिए तथा स्पष्ट किया कि प्रस्तावित चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय गाइडलाइन की कठोरता से पालना की जाए। याचिका में अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने बताया है कि, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने गत नौ सितंबर को वार्षिक चुनाव 18 नवम्बर को करवाने का आदेश दिया था। बी.सी.आई. सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय, "वन बार वन वोट" के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की शंका मात्र के आधार पर चुनावों पर रोक लगा दी, जबकि अभी तक सिर्फ चुनाव की तिथि ही तय हुई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि, बी.सी.आई. को बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है और पूर्व में भी हाईकोर्ट ने बार काउन्सिल आफ राजस्थान के चुनाव पर रोक के बी.सी.आई. के फैसले को रद्द किया था।

- हाई कोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के आदेश पर लगाई रोक।

हिन्दी की खिलाफत दक्षिण भारत की राजनीति का आधार बनेगी आगामी चुनावों में?

तमिलनाडू के मुख्यमंत्री स्टालिन ने गृह मंत्रालय के आधीन भाषा के मसले पर गठित संसदीय समिति की रिपोर्ट को आधार बनाकर केन्द्रीय सरकार व भाजपा को काफी खरी-खोटी सुनायी और धमकी भी दे डाली कि, भाजपा का भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस का 1960 के दशक में हुआ था, दक्षिण के हिन्दी विरोधी आंदोलन के कारण

- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, हिन्दी को उच्च शिक्षा में पढ़ने-पढ़ाने का माध्यम होना चाहिये। उच्च शिक्षा का मतलब, आई.आई.टी., आई.आई.एम., केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व एम्स से है।
- स्टालिन के अनुसार इससे दक्षिण भारत के लोग देश में सैकण्ड क्लास नागरिक हो जायेंगे।
- केन्द्रीय सरकार का यह कदम संविधान के भी खिलाफ होगा, क्योंकि संविधान में सभी क्षेत्रीय भाषाओं से बराबर का बर्ताव करने की व्यवस्था प्रदत्त की गई है।
- "हिन्दी को अंग्रेजी की जगह बिठाने से हिन्दी भाषी लोगों को नाजायज लाभ मिलेगा।"

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केन्द्र सरकार पर भाषा के मुद्दे पर फूट डालने वाला एजेंडा अपनाने का आरोप लगाते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि इस कोशिश को बंद करें, जो देश की एकता को नुकसान पहुँचा सकती है।

हाँ, अगर आई.आई.टी., आई.आई.एम. एम्स तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी ऊँचे पढ़ाई की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने की केन्द्र की कथित कोशिश के संबंध में मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो भाषा का मुद्दा सचमुच तथा सोच-समझकर 2024 के लोकसभा चुनावों की खातिर शुरू किया गया है।

सरकार के खुले इरादों, जो गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में निहित हैं, का हवाला देने वाली इस मीडिया रिपोर्ट के चंद घंटे बाद ही तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने सरकार की इस कथित कोशिश पर बड़ा सख्त प्रहार किया।

हाँ, तो यह भाषाई युद्ध सचमुच शुरू हो गया है तथा इसकी चिनगारियाँ आम चुनाव की तैयारियों के दौरे तक पहुँचेगी। हिन्दी को देश की साझा भाषा के रूप में "थोपने" तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा हिन्दी को एक सामान्य भाषा के रूप में अपनाने के खिलाफ तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मजबूती से खड़े हो गये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र की इस चेष्टा से दक्षिण भारतीय लोग दोयम दर्जे के नागरिक बन कर रह जायेंगे।

मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित इस रिपोर्ट पर, चेन्नई में जारी किये गये एक कठोर बयान के अंतर्गत तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने केन्द्र को राज्य में हुये हिन्दी-विरोधी आंदोलन की याद दिलाई तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वे देश में एक और भाषाई युद्ध न भड़काएं।

मीडिया के विभिन्न वर्गों के जरिये सामने आई "पार्लियामैन्ट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज" की विषय वस्तु की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए , स्टालिन ने कहा कि अगर यह क्रियान्वित हुई, तो गैर हिन्दी भाषी अपार जनसमूह उसके ही देश में दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में आयेगा।

उन्होंने कहा, "हिन्दी को थोपा जाना भारत की एकता के विरूद्ध है। भाजपा सरकार को अतीत में हुये हिन्दी-विरोधी आंदोलनों से सबक लेना चाहिये।" उन्होंने 1960 के दशक में हुये हिन्दी विरोधी आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि इन आंदोलनों के फलस्वरूप, कांग्रेस राज्य की सत्ता से बेदखल हो गई तथा उसके बाद से, कांग्रेस को राज्य कुछ सीटें पाने के लिये भी इस पर उस द्रविड़ पार्टी पर निर्भर रहना पड़ा है। इस समय, कांग्रेस डी.एम.के. (द्रमुक) पर निर्भर है तथा विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में उसकी गठबंधन पार्टनर है।

उल्लेखनीय है कि द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे ने तमिलनाडू में इकतरफा जीत हासिल की थी तथा 2019 के लोकसभा चुनावों में 39 लोकसभा सीटों में से एक के अलावा सभी सीटें जीत ली थीं। और अगर, इस भावनात्मक मुद्दे को एक बार फिर उसे उपलब्ध करा दिया जाता है, तो इश बात की पूरी-पूरी संभावना है कि डी.एम.के. अपने पूर्ववर्ती प्रदर्शन को 2024 के आम चुनावों में फिर से दोहरा सकती है।

स्टालिन ने ट्वीट किया, "भारत की विविधता को नकारते हुए, हिन्दी थोपने का भाजपा की केन्द्रीय सरकार का कड़ा दबाव एक खतरे की सूचना के रूप में आता दिखाई दे रहा है। "पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज" के ग्यारहवें खंड में मौजूद प्रस्ताव भारत की आत्म पर सीधा एवं खुला हमला है।"

स्टालिन ने कहा कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक खाद्य पदार्थ तथा एक संस्कृति को जबरदस्ती लादने की केन्द्र सरकार की मुद्रा भारत की एकता को प्रभावित करेगी। उन्होंने आगे कहा, "केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली "पार्लियामैन्ट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज" द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशें की गई हैं जो भारतीय संघ की एकता-अखंडता के लिये खतरा हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमेटी ने सिफारिश की है कि आई.आई.टी., आई.आई.एम., ए.आई.आई. एम.एस. (एम्स) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों जैसे सभी संस्थानों में निर्देश के माध्यम की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी प्रयुक्त की जाए।

स्टालिन ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए ध्यान दिलाया कि संविधान की आठवीं अनुसूची में तमिल सहित 22 भाषाएं हैं, जिन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पैनल ने भारत में समान भाषा के रूप में हिन्दी की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने प्रश्न किया कि "ऐसे परिदृश्य में केन्द्रीय मंत्री के नेतृत्व वाली कमेटी को यह सिफारिश करने की क्या जरूरत पड़ गई कि हिन्दी को भारत की सामान्य भाषा बना दिया जाए।

इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र में हिन्दी को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए, उन्होंने दावा किया कि हिन्दी को अनुचित व पक्षतापूर्ण एडवांटेज देना संविधान की भावना के खिलाफ है और यह अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव है।

केन्द्र की भाजपा सरकार पर संविधान की नितांत उपेक्षा कर हिन्दी को लगातार थोपने का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने कहा कि देश के लिए एक "कॉमन लैंग्वेज" का आदेश देना व्यवहारिक रूप से असंभव है तथा वह यह कहने के समान है कि सिर्फ हिन्दी भाषी ही भारत के संवैधानिक नागरिक हैं और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग देश के दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वाभाविक रूप से विभाजनकारी है।"

उन्होंने कहा कि देश का वास्तविक चरित्र- "अनेकता में एकता" है। भारत का चरित्र अनेकता में एकता है, अत: सभी भाषाओं को समान आदर मिलना चाहिए और सभी को अधिकारिक भाषाएं बनाना चाहिए।

स्टालिन ऐसा कहने वाले एक मात्र व्यक्ति हैं, लेकिन इस संदर्भ में वह अंतिम व्यक्ति नहीं होंगे क्योंकि भाषा मुद्दे पर केन्द्र सरकार के प्रकट रूख का दक्षिण भारतीय राज्यों और पश्चिम बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध सामने आने वाला है। ये तो कुछ नाम भर हैं।

नया चुनाव चिन्ह

- शिव सेना का शिंदे गुट अब तक पृथक क्षेत्रीय पार्टी बन गया है, इसे ना केवल अलग नाम मिला है, बल्कि "दो तलवार और ढाल" का चुनाव चिन्ह भी मिला है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को मंगलवार को अन्ततः "दो तलवार और एक ढाल" का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया और उनकी पार्टी का नाम होगा "बाला साहेबांची शिवसेना"।

ढाल-तलवार पूर्ववर्ती पीपुल्स डैमोक्रेटिक मूवमैंट के लिए आरक्षित था। उसकी वर्ष 2004 में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता रद्द कर दी गई और आगे जाकर उसे 26.12.2016 को सूची से हटा दिया गया था। चुनाव आयोग ने इसे एक स्वतंत्र चुनाव चिन्ह घोषित करते हुए वर्तमान उप चुनाव में उपयोग के लिए शिंदे गुट को आवंटित किया है, लेकिन यह तब ही है, जब तक कि शिव सेना और उसके पूर्व चुनाव चिन्ह के हक के विवाद में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता। हालांकि शिंदे गुट ने सूर्य बतौर चुनाव चिन्ह मांगा था, पर चुनाव आयोग ने यह मांग नहीं स्वीकार की।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908